समक्ष *ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और अशोक कुमार वर्मा, जे जे.*

प्रवर्तन निदेशालय, चंडीगढ़ आंचलिक अधिकारी, चंडीगढ़—प्रार्थी

बनाम

ओम प्रकाश चौटाला—उत्तरदाता

2020 का पीएमएलए-एपीपीएल-3

नवम्बर 17/2020

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 - धारा 2, 8(4), (6) और (8), 3, 26(4) और 35 - धन शोधन निवारण (न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा पुष्टि की गई कुर्क या जब्त संपत्तियों का कब्जा लेना) नियम, 2013 — नियम 5(5) - पुत्र/पोते की शादी के आधार पर कुर्क की गई संपत्ति, आवासीय मकान की अंतरिम बहाली की मांग करने वाली अपील - अपीलीय अधिकरण ने अंतनहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी और प्रवर्तन निदेशालय को संपत्ति की सील हटाने और कब्जा सौंपने का आदेश दिया— को चुनौती. — दलील है कि आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना है— आयोजित, धारा 26(4) कहता है कि ट्रिब्यूनल, पार्टियों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, ऐसे आदेश पारित कर सकता है जैसा कि वह उचित समझता है, पुष्टि करना, संशोधित करना या अपील किए गए आदेश को रद्द करना— यह अपील पर निर्णय लेने के अंतिम चरण में होगा. — जहां एक ट्रिब्यूनल को किसी विशेष मुद्दे या विषय से संबंधित अंतिम आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान की गई है, उसके पास उसी से संबंधित अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति है, जब तक कि इसके लिए एक विशिष्ट रोक न हो। — S.8 के संदर्भ में एकमात्र बार तब कदम उठाएगा जब विशेष न्यायालय के समक्ष मुकदमा शुरू हो गया हो, जो मामले में स्थिति नहीं है क्योंकि प्रतिवादी के खिलाफ अभी तक आरोप तय नहीं किए गए हैं. —ऐसा कुछ भी नहीं है जो ट्रिब्यूनल को कुर्क की गई संपत्ति की अस्थायी डी-सीलिंग का आदेश देने से रोकता है - यह शक्ति प्रकृति में विवेकाधीन है, और वैधानिक प्रावधानों और इसकी प्रयोज्यता की उचित समझ पर आधारित होना आवश्यक है, जिसमें इसका गैर-अनुपालन शामिल है. — गुण-दोष के आधार पर, यह माना गया कि ट्रिब्यूनल ने अंतरिम प्रार्थना के अनुदान के लिए आवेदन के जवाब में अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार नहीं किया है— ट्रिब्यूनल ने केवल संपत्ति को बहाल करने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्तियों का उल्लेख किया— तथ्यों का कोई संदर्भ नहीं दिया गया है या वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है– यह

आदेश को गूढ़, अधूरा और गैर-बोलने वाला बना देता है। — परिणामस्वरूप, अपील की अनुमति दी गई, आदेश को रद्द कर दिया गया, और मामले को नए सिरे से निर्णय के लिए अपीलीय प्राधिकारी को भेज दिया गया।

निर्धारित किया गया कि प्राथमिक प्रश्न, जिसे पक्षों के वकील द्वारा उद्धृत दलीलों, तथ्यों और कानून के आलोक में जाने की आवश्यकता है, अपीलीय न्यायाधिकरण की शक्ति के संबंध में एक आदेश पारित करने के संबंध में है, अंतरिम राहत के लिए आवेदन की अनुमति अपील के लंबित रहने के दौरान, जैसे कि थोड़े समय के लिए किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए संपत्ति की बहाली, जैसा कि वर्तमान मामले में है।

(पैरा 8)

निर्धारित किया गया इसके लिए अधिनियम की धारा 26 और 35 के प्रावधानों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। अधिनियम की धारा 26(4) के अवलोकन से पता चलता है कि अपीलीय अधिकरण, अपील प्राप्त होने पर, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझे, अपील किए गए आदेश की पुष्टि, संशोधन या उसे रद्द कर सकता है। इसलिए, क़ानून की आवश्यकता यह है कि अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए एक नोटिस अनिवार्य है। यह स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 35 (1) के प्रावधानों के अनुरूप है, जहां अपीलीय न्यायाधिकरण को सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं कहा गया है और बल्कि, मार्गदर्शक सिद्धांत प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत होंगे लेकिन इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन होंगे। शेष प्रक्रिया अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा विनियमित की जाएगी क्योंकि ऐसी शक्तियां प्रदान की गई हैं यह। अपीलीय न्यायाधिकरण को प्रदत्त शक्तियां अपील किए गए आदेश की पुष्टि, संशोधन या उसे रद्द करने के लिए हैं और यह अपील पर निर्णय लेने के अंतिम चरण में होगा। जहां तक अपील के लंबित रहने के दौरान पारित किए जाने वाले आदेशों से संबंधित पहलू का संबंध है, अपीलीय अधिकरण के विवेकाधिकार पर छोड़ दिया गया है कि वह उस पर ऐसे आदेश पारित करे जो वह उचित समझे लेकिन इस शर्त के साथ कि अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाए। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलीय प्राधिकारी संपत्ति से संबंधित आदेश पारित नहीं कर सकता है, जो अंतरिम उपाय के रूप में अपील की विषय वस्तु है, जहां यह प्रथम दृष्टया संतुष्ट है कि अपराध के कमीशन के संबंध में रिकॉर्ड पर स्पष्ट त्रुटि है या कुर्की के दौरान अपनाई गई प्रक्रिया में और प्रश्नगत संपत्ति का कब्जा है। यदि अपीलकर्ता के वकील द्वारा उठाए गए तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो अधिनियम के तहत प्रदान किए गए अपील के प्रावधान को निरर्थक और केवल औपचारिकता

या दिखावा माना जाएगा। जहां अपीलीय न्यायाधिकरण को किसी विशेष मुद्दे या विषय से संबंधित अंतिम आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान की गई है, उसके पास उसी से संबंधित अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति है, जब तक कि इससे संबंधित कोई विशिष्ट रोक न हो। अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, पक्षकारों के वकीलों द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है, जो इस तरह के आदेश को पारित करने से रोकेगा, अधिनियम की धारा 26 (4) में प्रयुक्त शब्द को 'ऐसे आदेश पारित करें जो वह उचित समझता है' को निरर्थक के रूप में प्रस्तुत करता है क्योंकि यह अपीलीय प्राधिकरण को योग्य मामलों में अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए पर्याप्त शक्तियां देता है। हालांकि, क़ानून के प्रावधान।

(पैरा 8)

निर्धारित किया गया कि एकमात्र बार, यदि कोई हो, जिसे अधिनियम की धारा 8 के संदर्भ में प्रतिवादी के वकील द्वारा पेश किया गया है, केवल वहीं कदम उठाएगा जहां विशेष न्यायालय के समक्ष मुकदमा शुरू हो गया है, जो वर्तमान मामले में, स्वीकार्य रूप से स्थिति नहीं है क्योंकि आज तक प्रतिवादी के खिलाफ कोई आरोप तय नहीं किया गया है। इसलिए, विशेष न्यायालय की उक्त शक्ति इस स्तर पर किसी भी मामले में लागू नहीं होगी, जो फिर से एक उपयुक्त मामले में देखा जाने वाला पहलू है।

(पैरा 9)

निर्धारित किया गया, कि अपीलकर्ता के लिए विद्वान वकील का तर्क कि न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित करने के बाद, एक संपत्ति की कुर्की के आदेश की पुष्टि करते हुए, धारा 5 के तहत कुर्क की गई संपत्ति का कब्जा लेने का अधिदेश देता है, यह कहने के लिए पर्याप्त है कि यह जनादेश केवल प्रवर्तन निदेशालय से संबंधित और लागू है, जो अपीलीय न्यायाधिकरण को उक्त संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त करने के लिए आदेश पारित करने से नहीं रोकता है। मामले के दिए गए तथ्य और परिस्थितियां और वह भी थोड़े समय के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है जो अपीलीय न्यायाधिकरण को कुर्क की गई संपत्ति को डी-सील करने का आदेश देने से रोक सके और वह भी सीमित अवधि के लिए। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस तरह की शक्ति का प्रयोग स्पष्ट रूप से उन तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अधिनिर्णय का विषय होगा जहां अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा इस तरह के विवेक का प्रयोग किया गया है। यद्यपि यह शक्ति विवेकाधीन प्रकृति की है, परंतु यह अपेक्षित है कि वह संविधि के उपबंधों के उचित मूल्यांकन और इसकी प्रयोज्यता पर आधारित हो, जिसमें इसका अनुपालन न किया जाना शामिल है। यह अंतरिम आदेश पारित करने या थोड़े समय के लिए अंतरिम राहत देने के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण के अधिकार

क्षेत्र के संबंध में मूल मुद्दे का जवाब देता है और वह भी एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए।

(पैरा 10)

अरविंद मौदगिल, भारत सरकार के वरिष्ठ वकील करण सेठी, कृतिन शर्मा और देविंदर पाल, *अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता।*

अशोक अग्रवाल, सीनियर एडवोकेट गौरव मोहंता और मुकुल अग्रवाल, एडवोकेट, प्रतिवादी के लिए।

ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, जे।

1. यह अपील अपीलीय न्यायाधिकरण, धन शोधन निवारण अधिनियम, नई दिल्ली द्वारा अभय सिंह चौटाला द्वारा प्रस्तुत दो आवेदनों पर अपीलीय न्यायाधिकरण, धन शोधन निवारण अधिनियम, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.10.2020 के खिलाफ की गई है, जिसमें एक ओम प्रकाश चौटाला के पावर ऑफ अटॉर्नी धारक/प्रतिनिधि के रूप में, जिन्होंने अपील की थी और दूसरा अपनी व्यक्तिगत क्षमता में, ग्राम तेजाखेड़ा में खेवट संख्या 97/98/99 और 104 वाली भूमि पर कुर्क संपत्ति यानी आवासीय घर की अंतरिम बहाली की मांग की थी। तहसील डबवाली, जिला सिरसा, हरियाणा ने इस आधार पर कि प्रतिवादी के पोते और आवेदक के बेटों का विवाह 27.11.2020 और 30.11.2020 को होना है। 15.11.2020 से 30.11.2020 के बीच कुर्क की गई संपत्ति की अंतरिम बहाली के लिए प्रार्थना की गई, जिसमें समारोह से पहले और बाद में संपत्ति का उपयोग करने और खाली करने की तैयारी के लिए अतिरिक्त 15 दिन का समय दिया गया। पक्षों की सुनवाई के बाद, अपीलीय न्यायाधिकरण ने प्रवर्तन निदेशालय (यहां अपीलकर्ता) को 06.11.2020 तक कुर्क की गई संपत्ति को डी-सील करने और प्रतिवादी-ओम प्रकाश चौटाला/हस्तक्षेपकर्ता अभय सिंह चौटाला को पूर्वोक्त विवाह के उद्देश्य से उसका कब्जा सौंपने का निर्देश देते हुए उक्त आवेदनों को आंशिक रूप से अनुमति दी है, इस शर्त के अधीन कि वे 07.12.2020 को या उससे पहले अपीलकर्ता को कब्जा वापस सौंप देंगे। जो इसके बाद अगले आदेश तक उक्त संपत्ति को सील कर सकते हैं।

2. संपत्ति की बहाली के लिए अंतरिम प्रार्थना का विरोध करते हुए अपीलकर्ता द्वारा लिया गया मूल आधार यह था कि अपीलीय न्यायाधिकरण के पास धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 8 (8) के प्रावधानों के आलोक

में संपत्ति को बहाल करने की कोई शक्ति नहीं थी, क्योंकि उक्त शक्ति विशेष न्यायालय को प्रदान की गई है, जो उक्त न्यायालय के समक्ष दायर किए गए आरोप पत्र में विचारण से समाप्त हो गया है। आगे यह दबाव डाला गया कि अपीलीय अधिकरण के पास अंतरिम राहत का ऐसा आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार नहीं था और इसलिए उक्त आदेश पारित नहीं किया जा सका, जिसे अपीलीय अधिकरण द्वारा यह कहते हुए नकार दिया गया कि यदि संपत्ति का कब्जा कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना लिया जाता है तो उसे ऐसा करने की अंतनहित शक्तियां प्राप्त हैं।

3. उक्त आदेश को चुनौती देते समय, अपीलकर्ता द्वारा जो आधार लिया गया है, वह यह है कि अधिनियम के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो आरोपी के उपयोग के लिए कुर्क संपत्ति की अस्थायी डी-सीलिंग की अनुमति देता है। आगे यह भी दावा किया गया है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 के आलोक में, धन शोधन के अपराध के लिए कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान संपत्ति का उपयोग अनुमेय नहीं है। एक बार जब उक्त संपत्ति का उपयोग स्वयं धन शोधन के अपराध में शामिल हो जाता है, तो अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा ऐसी संपत्ति के उपयोग की अनुमति देने वाला आदेश पारित नहीं किया जा सकता था। आगे यह कहा गया है कि अधिनियम की धारा 3 (ii) के अनुसार, अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि तब तक जारी रहती है जब तक कि कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से छिपाने या कब्जे या अधिग्रहण आदि के माध्यम से उक्त आय का आनंद नहीं ले रहा है। इसलिए, यह कहा जाता है कि अभियुक्त को अपराध की आय का आनंद लेने से प्रतिबंधित किया गया है और इस प्रकार, अपीलीय न्यायाधिकरण ऐसा अंतरिम आदेश पारित नहीं कर सकता था। एक आधार यह भी लिया गया है कि प्रवर्तन निदेशालय, चंडीगढ़ द्वारा केवल 50% आवासीय घर को सील/कुर्क किया गया है और चूंकि केवल प्रतिवादी के स्वामित्व में आने वाले हिस्से को सील कर दिया गया था, इसलिए इसे डी-सील करने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि माना जाता है कि शेष घर अभय सिंह चौटाला के कब्जे में है। अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने न्यायालय को अधिनियम के इरादे, उद्देश्य और योजना पर दबाव डालने के लिए क़ानून के विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख किया है ताकि यह तर्क दिया जा सके कि एक बार कुर्क की गई संपत्ति, जो अपराध की आय पाई जाती है, उसे अंतरिम उपाय के रूप में, डी-सील करने और कब्जा सौंपने का आदेश नहीं दिया जा सकता है।

4. वकील द्वारा धारा 2 (डी) 'कुर्की', 2 (यू) 'अपराध की आय', 2 (वी) 'संपत्ति', 2 (जेडए) 'हस्तांतरण' और 2 (जेडबी) 'मूल्य' में दी गई परिभाषाओं पर प्राथमिक जोर दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के संबंध में न्यायालय को प्रभावित करने के लिए धारा 3 पर भरोसा किया गया है, जहां उक्त दागी संपत्ति के उपयोग को भी अपराध के रूप में उल्लेख किया गया है, एक गतिविधि जो उक्त संपत्ति के कब्जे पर जारी है, वह भी उक्त अपराध के अंतर्गत आती है। इस आधार पर यह दावा किया जाता है कि इस तरह के अंतरिम आदेश को पारित करके, अपीलीय न्यायाधिकरण एक अपराध को कायम रखेगा, जो कानून के मूल जनादेश के खिलाफ जाएगा। अधिनियम की धारा 8 (4) का उल्लेख करते हुए, यह दावा किया गया है कि निर्णायक प्राधिकारी द्वारा कुर्की के आदेश की पुष्टि पर, प्रवर्तन निदेशालय को अधिनियम की धारा 5 के तहत संलग्न संपत्ति का तुरंत कब्जा लेने के लिए अनिवार्य किया गया है। अधिनियम की धारा 8 (6) का उल्लेख करते हुए, यह दावा किया गया है कि विशेष न्यायालय के पास मुकदमे के समापन के बाद ही संपत्ति को मुक्त करने की शक्ति है, जहां मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का कमीशन नहीं पाया गया है या संपत्ति उसी में शामिल नहीं है। अधिनियम की धारा 26 (4) का उल्लेख करते हुए, यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलीय न्यायाधिकरण को हालांकि ऐसे आदेश पारित करने की शक्तियां दी गई हैं जो वह उचित समझता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अंतरिम आदेश के माध्यम से, यह एक अपराध के कमीशन को बनाए रखेगा, जो कानून में स्वीकार्य नहीं है। अपीलकर्ता के वकील द्वारा निम्नलिखित निर्णयों का संदर्भ दिया गया है: -

i. ***डॉ.वी.एम.गणेश*** *बनाम* ***रजिस्ट्रार, अपीलीय अधिकरण, नई दिल्ली और अन्य***[1]

ii. ***बी. राम राजू*** *बनाम* ***भारत संघ (यूओआई), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग और अन्य***[2]

iii. ***प्रवर्तन निदेशालय के उप निदेशक दिल्ली*** *बनाम* ***एक्सिस बैंक और अन्य***, Crl.A.143/2018 & Crl.M.A.2262/2018, का फैसला 02 अप्रैल, 2019 को किया गया

[1] (2019) 4 सीटीसी 222

[2] (2011) 108 एससी एल 491 (एपी)

iv. ***जे. शेखर** बनाम **भारत संघ और अन्य***[3]

v. ***पी. चिदंबरम बनाम** प्रवर्तन निदेशालय, **जमानत अपील.2718/2019, निर्णय दिनांक 15.11.2019***

5. दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने धारा 8 (1) के दूसरे परंतुक का हवाला देते हुए कहा है कि निर्णायक प्राधिकरण को नोटिस जारी करने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी कि यह संयुक्त रूप से संपत्ति रखने वाले सभी व्यक्तियों को दिया जाए। यह विवादित नहीं है कि अभय सिंह चौटाला सहित संपत्ति के अन्य संयुक्त धारकों को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। चूंकि कुर्की का आदेश, जैसा कि न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा पुष्टि की गई है, अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, कुर्की की पुष्टि करने वाला आदेश कायम नहीं रह सकता है और इसलिए अपीलीय अधिकरण ने अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए सही कार्यवाही की है। उन्होंने दावा किया कि माना जाता है कि अभय सिंह चौटाला कार्यवाही में पक्षकार नहीं थे, उन्होंने एक इच्छुक पक्ष होने के नाते, उन्हें एक हस्तक्षेपकर्ता के रूप में शामिल करने के लिए एक आवेदन दिया था, जिसे अंतरिम राहत के लिए आवेदन की अनुमति देने के अलावा, आक्षेपित आदेश के तहत आवेदन की अनुमति दी गई है, लेकिन उन्हें वर्तमान अपील में पक्षकार प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं किया गया है। यह आगे मजबूत करता है कि अपीलकर्ता द्वारा ओम प्रकाश चौटाला की सीमा तक सीमित आदेश को चुनौती दी गई है। यह दावा किया जाता है कि चूंकि यह एक सामान्य आदेश है, इसलिए अपील वर्तमान रूप में बनाए रखने योग्य नहीं होगी, जिसके लिए नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 99 के प्रावधानों पर भरोसा किया गया है। अधिनियम की धारा 2 (यू) का उल्लेख करते हुए, जो अपराध की आय को परिभाषित करता है, विद्वान वरिष्ठ वकील ने भाषा पर जोर देकर कहा है कि या तो अचल संपत्ति कुर्क की जा सकती है या ऐसी किसी भी संपत्ति के मूल्य को अपराध की आय के रूप में लिया जा सकता है। उन्होंने धन-शोधन निवारण (न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा कुर्क या जमी हुई संपत्तियों का कब्जा लेना) नियम, 2013 के नियम 5 (5) के संदर्भ में इस पहलू का उल्लेख किया है, जिसमें न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा पुष्टि की गई अचल संपत्ति के संबंध में भूमि, भवन, मकान, फ्लैट आदि के रूप में है और संयुक्त स्वामित्व के अधीन है, प्राधिकृत अधिकारी धन शोधन में शामिल होने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमानित संपत्ति में संबंधित

[3] 2018 सीआरएल एलजे 1720

व्यक्ति के हिस्से के मूल्य की सीमा तक सावधि जमा के समतुल्य मूल्य को स्वीकार कर सकता है। इस आधार पर, वह दावा करता है कि यहां प्रतिवादी ने अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलकर्ता-प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय के साथ एफडीआर के रूप में 1,99,87,300/- रुपये की राशि जमा करने का वचन दिया था, ताकि अपील के लंबित रहने के दौरान कुर्क संपत्ति की बहाली हो सके। इसलिए, उनका तर्क है कि संपत्ति का कब्जा लेना हमेशा अनिवार्य नहीं होता है, जैसा कि अपीलकर्ता के वकील द्वारा दावा किया गया है।

6. जहां तक अंतरिम आदेश पारित करने के लिए अपीलीय अधिकरण के क्षेत्राधिकार का संबंध है, जैसा कि आक्षेपित किया गया है, अधिनियम की धारा 35 का संदर्भ दिया गया है, जो अपीलीय अधिकरण की प्रक्रिया और शक्तियों से संबंधित है। यह दावा किया जाता है कि अपीलीय न्यायाधिकरण के पास अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति है और एकमात्र मार्गदर्शक सिद्धांत प्राकृतिक न्याय है। अधिनियम की धारा 26 (4) का उल्लेख करते हुए, यह दावा किया गया है कि अपीलीय न्यायाधिकरण, संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझता है, अपील किए गए आदेश की पुष्टि, संशोधन या उसे रद्द कर सकता है। इस आधार पर, वह दावा करता है कि जहां अपीलीय न्यायाधिकरण ने पाया है कि संपत्ति का कब्जा लेते समय कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा अपील किए गए आदेश की पुष्टि नहीं की गई है, तो पारित अंतरिम आदेश पूरी तरह से न्यायसंगत होगा और कानून के अनुसार, जो अधिनियम की धारा 26 (4) के तहत प्रदत्त विवेक के भीतर आएगा। अपीलीय न्यायाधिकरण के पास ऐसा करने के लिए अंतर्निहित शक्तियां हैं और उसी का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश को अस्थिर नहीं कहा जा सकता है।

7. जहां तक अपीलकर्ता के वकील के इस दावे का संबंध है कि अपीलीय न्यायाधिकरण के पास संपत्ति को अस्थायी रूप से बहाल करने की शक्ति नहीं थी और केवल विशेष न्यायालय ही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसा कर सकता था, यह दावा किया जाता है कि मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हुआ है क्योंकि पक्षों के बीच यह स्वीकार किया गया है कि विशेष न्यायालय द्वारा आरोप तय किए जाने बाकी हैं। यदि विचारण शुरू नहीं हुआ है, तो शक्ति केवल अपीलीय न्यायाधिकरण के पास निहित है। इसलिए, यह दावा किया जाता है कि कानून के अनुसार होने के कारण आक्षेपित आदेश, इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की मांग नहीं

करता है। प्रतिवादी के वकील ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया है: -

i. ***द मैनेजमेंट होटल इम्पीरियल, नई दिल्ली और अन्य*** *बनाम* ***होटल वर्कर्स यूनियन***[4]

ii. ***इलाहाबाद बैंक, कलकत्ता*** *बनाम* ***राधा कृष्ण मैती***[5]

iii. ***इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड*** *बनाम* ***ग्रेपको इंडस्ट्रियल लिमिटेड***[6]

iv. ***ग्रिंडलेज बैंक लिमिटेड*** *बनाम* ***केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण और अन्य***[7]

v. ***ओम प्रकाश चौटाला*** *बनाम* ***संयुक्त निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, चंडीगढ़,*** एफपीए-पीएमएलए-3382/सीएचडी/2019, निर्णय 23.12.2019

vi. ***जी.अमुधा*** *बनाम* ***अपीलीय ट्रिब्यूनल धन शोधन निवारण अधिनियम, नई दिल्ली और अन्य के तहत,*** 2017 की डब्ल्यूपी संख्या 6159, 14.03.2017 को फैसला दिया गया

vii. ***मायड्रीम प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड*** (क) क्या यह सच है कि *भारत सरकार ने सीमा* ***शुल्क (आयात) के मामले में सीमा शुल्क (आयात) के मामले में प्रतिवाद किया है***[8]

viii. ***जगतू*** *बनाम* ***सूरज मल और अन्य***[9]

ix. ***चमन लाल*** *बनाम* ***पंजाब राज्य और अन्य***[10]

x. ***रतिलाल भांजी मिठानी*** *बनाम* ***महाराष्ट्र राज्य और अन्य***[11]

xi. ***V.C.Shukla*** *versus* ***State through C.B.I***.[12]

---

[4] 1959 एआईआर (एससी) 1342
[5] 1999 एआईआर (एससी) 3426
[6] 1999 एआईआर (एससी) 1975
[7] (1981) एआईआर (एससी) 606
[8] (2018) 9 जीएसटीएल 354
[9] (2010) 13 एससीसी 769
[10] (2014) 15 एससीसी 715
[11] (1979) एआईआर (एससी) 94
[12] (1980) AIR (SC) 962

xii. ***यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मेजर जनरल मदन लाल यादव (सेवानिवृत्त)***[13]

xiii. ***उत्तर प्रदेश राज्य और दूसरा*** *बनाम* ***सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड और अन्य***[14]

xiv. ***मैसर्स हैदर कंसल्टिंग (यूके) लिमिटेड (क) क्या यह सच है कि मुख्य अभियंता के माध्यम से उड़ीसा राज्य के*** *राज्यपाल बनाम* ***राज्यपाल, उड़ीसा राज्य के मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है।***[15]

8. हमने पक्षों के वकीलों को सुना है और उनकी सहायता से मामले के रिकॉर्ड के साथ-साथ ऊपर उल्लिखित निर्णयों का भी अध्ययन किया है।

9. प्राथमिक प्रश्न, जिसे पक्षकारों के वकील द्वारा उद्धृत दलीलों, तथ्यों और कानून के आलोक में जाने की आवश्यकता है, अपीलीय न्यायाधिकरण की शक्ति के संबंध में एक आदेश पारित करने के संबंध में है, अपील के लंबित रहने के दौरान अंतरिम राहत के लिए आवेदन की अनुमति देना, जैसे कि थोड़े समय के लिए किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए संपत्ति की बहाली, जैसा कि वर्तमान मामले में है।

10. इसके लिए अधिनियम की धारा 26 और 35 के प्रावधानों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अधिनियम की धारा 26(4) के अवलोकन से पता चलता है कि अपीलीय अधिकरण, अपील प्राप्त होने पर, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझे, अपील किए गए आदेश की पुष्टि, संशोधन या उसे रद्द कर सकता है। इसलिए, क़ानून की आवश्यकता यह है कि अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए एक नोटिस अनिवार्य है। यह स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 35 (1) के प्रावधानों के अनुरूप है, जहां अपीलीय न्यायाधिकरण को सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं कहा गया है और बल्कि, मार्गदर्शक सिद्धांत प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत होंगे लेकिन इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन होंगे। शेष प्रक्रिया अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा विनियमित की जाएगी क्योंकि ऐसी शक्तियां प्रदान की गई हैं यह। अपीलीय न्यायाधिकरण को प्रदत्त शक्तियां अपील किए गए आदेश की पुष्टि, संशोधन या उसे रद्द करने के लिए हैं और यह अपील

---

[13] (1996) एआईआर (एससी) 1340

[14] (1991) 4 एससीसी 139

[15] (2015) एआईआर (एससी) 856

पर निर्णय लेने के अंतिम चरण में होगा। जहां तक अपील के लंबित रहने के दौरान पारित किए जाने वाले आदेशों से संबंधित पहलू का संबंध है, अपीलीय अधिकरण के विवेकाधिकार पर छोड़ दिया गया है कि वह उस पर ऐसे आदेश पारित करे जो वह उचित समझे लेकिन इस शर्त के साथ कि अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाए। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलीय प्राधिकारी संपत्ति से संबंधित आदेश पारित नहीं कर सकता है, जो अंतरिम उपाय के रूप में अपील की विषय वस्तु है, जहां यह प्रथम दृष्टया संतुष्ट है कि अपराध के कमीशन के संबंध में रिकॉर्ड पर स्पष्ट त्रुटि है या कुर्की के दौरान अपनाई गई प्रक्रिया में और प्रश्नगत संपत्ति का कब्जा है। यदि अपीलकर्ता के वकील द्वारा उठाए गए तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो अधिनियम के तहत प्रदान किए गए अपील के प्रावधान को निरर्थक और केवल औपचारिकता या एक छलावा प्रदान किया जाएगा। जहां अपीलीय न्यायाधिकरण को किसी विशेष मुद्दे या विषय से संबंधित अंतिम आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान की गई है, उसके पास उसी से संबंधित अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति है, जब तक कि इससे संबंधित कोई विशिष्ट रोक न हो। अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, पक्षकारों के वकीलों द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है, जो इस तरह के आदेश को पारित करने से रोकेगा, अधिनियम की धारा 26 (4) में प्रयुक्त शब्द को 'ऐसे आदेश पारित करें जो वह उचित समझता है' को निरर्थक के रूप में प्रस्तुत करता है क्योंकि यह अपीलीय प्राधिकरण को योग्य मामलों में अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए पर्याप्त शक्तियां देता है। हालांकि, क़ानून के प्रावधान।

11. एकमात्र बार, यदि कोई हो, जिसे अधिनियम की धारा 8 के संदर्भ में प्रतिवादी के वकील द्वारा पेश किया गया है, केवल वहीं कदम उठाएगा जहां विशेष न्यायालय के समक्ष मुकदमा शुरू हो गया है, जो वर्तमान मामले में, स्वीकार्य रूप से स्थिति नहीं है क्योंकि आज तक प्रतिवादी के खिलाफ कोई आरोप तय नहीं किए गए हैं। इसलिए, विशेष न्यायालय की उक्त शक्ति इस स्तर पर किसी भी मामले में लागू नहीं होगी, जो फिर से एक उपयुक्त मामले में देखा जाने वाला पहलू है।

12. अपीलकर्ता के लिए विद्वान वकील का तर्क है कि न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित करने के बाद, एक संपत्ति की कुर्की के आदेश की पुष्टि करते हुए, धारा 5 के तहत संलग्न संपत्ति का कब्जा लेने का जनादेश देता है, यह कहने के लिए पर्याप्त है कि यह जनादेश केवल प्रवर्तन निदेशालय से संबंधित और लागू है, जो अपीलीय न्यायाधिकरण को उक्त

संपत्ति की रिहाई के लिए आदेश पारित करने से नहीं रोकता है ताकि अस्थायी रूप से संलग्न संपत्ति को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए और वह भी थोड़े समय के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है जो अपीलीय न्यायाधिकरण को कुर्क की गई संपत्ति को डी-सील करने का आदेश देने से रोक सके और वह भी सीमित अवधि के लिए। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस तरह की शक्ति का प्रयोग स्पष्ट रूप से उन तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अधिनिर्णय का विषय होगा जहां अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा इस तरह के विवेक का प्रयोग किया गया है। यद्यपि यह शक्ति विवेकाधीन प्रकृति की है, परंतु यह अपेक्षित है कि वह संविधि के उपबंधों के उचित मूल्यांकन और इसकी प्रयोज्यता पर आधारित हो, जिसमें इसका अनुपालन न किया जाना शामिल है। यह अंतरिम आदेश पारित करने या थोड़े समय के लिए अंतरिम राहत देने के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र के संबंध में मूल मुद्दे का जवाब देता है और वह भी एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए।

13. अब वर्तमान मामले के गुण-दोष पर आते हैं। बेशक, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा शुरू की गई कार्यवाही अकेले प्रतिवादी के खिलाफ है और विचाराधीन संपत्ति एक संयुक्त संपत्ति है, जिसमें से एक सह-शेयरधारक अभय सिंह चौटाला हैं, जो वर्तमान अपील के पक्षकार नहीं हैं। आक्षेपित आदेश दिनांक 22.10.2020 के अनुसार, एक आवेदन, जिसे अभय सिंह चौटाला द्वारा एक हस्तक्षेपकर्ता के रूप में पक्षकार के रूप में पेश किए जाने के लिए पसंद किया गया है, को अनुमति दी गई है और उन्हें अपीलकर्ता नंबर 2 के रूप में शामिल किया गया है। कुर्क की गई संपत्ति की अंतरिम बहाली की मांग के उनके आवेदन को प्रतिवादी-ओम प्रकाश चौटाला द्वारा उसी राहत के लिए आवेदन के साथ स्वीकार कर लिया गया है। चूंकि ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ अपील दायर की गई है, इसलिए यह अदालत केवल उनके खिलाफ अपील पर विचार कर रही है।

14. अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश का अवलोकन स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि अंतरिम प्रार्थना के अनुदान के लिए आवेदन के जवाब में अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दे पर विशेष रूप से अपीलकर्ता द्वारा संदर्भित और भरोसा किए गए वैधानिक प्रावधानों के संबंध में विचार नहीं किया गया है। अपीलीय न्यायाधिकरण ने आदेश में बस इतना कहा है कि कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना संपत्ति का कब्जा लेने की स्थिति में संपत्ति को बहाल करने की अंतर्निहित शक्तियां हैं। आक्षेपित आदेश में संविधि के विशिष्ट प्रावधानों का अनुपालन न करने के संबंध में

कोई कारण नहीं बताया गया है। इस तथ्य का कोई संदर्भ नहीं दिया गया है कि कैसे, कब और कहां कानून के सांविधिक प्रक्रियात्मक और अनिवार्य उपबंधों का अनुपालन न किया गया है अथवा उनका उल्लंघन किया गया है। यह अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश को कानून में गूढ़, अधूरा और गैर-बोलने वाला बनाता है, इस तरह के आदेश को पारित करने के लिए किसी भी औचित्य के बिना। ऐसा प्रतीत होता है कि दिमाग का उपयोग न किया गया है, जिससे आदेश को रद्द करने के लिए उत्तरदायी बनाया जा सकता है।

15. उपरोक्त के मद्देनजर, वर्तमान अपील की अनुमति दी जाती है और अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 22.10.2020 के आक्षेपित आदेश को एतद्द्वारा अलग रखा जाता है और मामले को प्रतिवादी की प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए कानून के अनुसार नए सिरे से निर्णय के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण को भेज दिया जाता है।

16. पक्षकारों को अपने वकील के माध्यम से 18.11.2020 को अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया जाता है।

17. चूंकि मुख्य अपील की स्वीकार कीजाती है, इसलिए लंबित आवेदनों पर कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रजत अरोड़ा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी